(ग) उनके मंत्रालय द्वारा बिहार में ऐसे कौन-कौन से शहर हैं जिनके और सुधार और विकास के लिए उनका कोई अध्ययन किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी०के० थुंगन) (क) से (ग) शहरी विकास राज्य का विषय है तथा इस मंत्रालय के पास राज्यों और संघ राज्य क्षत्रों को देने के लिए कोई अलग कोष नहीं है। इस मंत्रालय ने बिहार राज्य के पटना शहर के लिए कोई विकास योजनाएं स्वीकृत नहीं की है। शहरी विकास मंत्रालय ने बिहार राज्य में किसी शहर का अध्ययन नहीं किया है।

Availability of Timber in the country

1503. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the estimated quantity of timber available in the country;

(b) whether it is a fact that Government have decided to reduce the use of timber in its public building programmes;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether any alternatives have been explored as substitute for timber; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) According to the State of Forest Report, 1987, the estimated sustainable annual production of timber from forests is 12.0 million cubic metre:

(b) Yes, Sir.

(c) The cutting of trees for use of timber in construction industry leads to depletion of forest cover, resulting in ecological degradation. Therefore, such a decision was taken with the objective of environmental preservation.

(d) Yes, Sir, a number of substitutes based on agroindustrial wastes, Cement, PVC and metal composites have been developed as suitable alternatives for different types of building applications.

(e) Various agro-industrial waste materials like rice-husk, cotton stalk, jute stick, bagasse, red mud coir fibre sisal fibre are being utilised for the manufacture of alternative reconstituted panel board to replace timber. Other materials such as plastic, iron & steel, Cement Concrete, aluminium and ferro cmeent are also being manufactured and used for replacing timber components in the construction of houses for various categories.

सरोजनी नगर, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सामने बने हुए पाकेट की शोचनीय स्थिति

1504. **श्री रामदेव भंडारी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजनी नगर स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के निकट ब्लाक "ए" में बने हुए आवासीय क्वार्टरों के बीच स्थित पार्क की स्थिति शोचनीय बनी हुई है और वहां पर आवारा पशु घूमते रहते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन पार्कों में भवन सामग्री का ढेर लगा रहता है जिससे वहां रहने वाले लोगों को अत्यधिक असुविधा हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इन पार्कों के नियमित रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी०के० थुंगन) : (क) सरोजनी नगर स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछताछ कार्यालय के समीप ए-ब्लॉक में कोई पार्क नहीं है। यह ब्लॉक पिलंजी गांव के पास स्थित है और गांव तथा ए-ब्लाक के बीच भूमि के कई छोटे प्लाट हैं। ग्रामीणों के लिए खुले छोड़े गए दरवाजों से आवारा मवेशी इन प्लाटों से गुजरते हैं।

(ख) गांव के निवासियों द्वारा इन भूखण्डों में भवन सामग्री और कूड़ाकरकट फेंक दिये जाते हैं। पिलंजी गांव और ए-ब्लाक सरोजनी नगर के बीच केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा एक दिवार बनवाई गई है ताकि ग्रामीण द्वारा, खुले भू-खंडों के दुरुपयोग को कम किया जा सके।

(ग) मवेशियों को इन प्लाटों में न घूमने देने का दायित्व मूलत: ग्रामीणों का है। वित्तीय दवाबों के कारण, गांव तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की भूमि के बीच के मार्ग को पूर्णत: सील करना व्यवहारिक नहीं है।

Lease cancellation of MIG flat, Ashok Vihar, Delhi

1505. SHRI MAHESHWAR SINGH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to Unstarred Question 2949 answered in the Rajya Sabha on 11h December; 1992 and state;

(a) whether the formalities regarding lease cancellation of flat No. 31 (MIG) Pocket 'A' Phase III Ashok Vihar, Delhi have since been completed?

(b) if so, what are the details thereof;

(c) if not, what are the reasons thereof; and

(d) by when the formalities are likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) As reported by DDA, Yes Sir:

(b) (i) The show cause notice was issued on 20.12.91.

(ii) Final show cause notice was issued on 21.2.92.

(iii) Cancellation letter was issued on 4.12.92.

(c) Not applicable.

(d) Not applicable.

Congestion and population growth in cites

1506. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are Government's plans to control congestion and population growth in cities;

(b) whether there are any guidelines to States to follow in this regard;

(c) whether a system of incentives and disincentives would be introduced to direct proper growth of cities and towns;

(d) whether any conference has been held with State Governments to evolve a concurrent policy on the subject; and

(e) the details of such conferences and the resultant policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) (a) to (e) The Scheme of Integrated Development of Small and Medium Towns (IDSMT) was introduced in 1979-80 for achieving balanced urban development in the